Corporation of Delhi had sent it to Delhi Administration.

(b) and (c). The slum tenements will be sold to allottees in accordance with the orders contained in Ministry's letter dated 2nd/3rd August, 1963. As regards J.J. Plots, it has been decided to review the matter.

(d) No time limit can be laid down as this would depend upon the finalisation of documents of lease-cum-sale agreement and calculation of the details of cost of these tenements.

राजघाट बांध के माध्यम से भूमि की सिंचाई

3129. **श्री लक्ष्मीनारायण नायक :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रस्तावित योजना के अनुसार टीकमगढ़ जिले की 65,000 एकड़ भूमि की राजघाट बांध से सिंचाई की जानी थी जब कि इस समय केवल 60,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है और जिले के लोगों में असंतोष है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : राजघाट नहर से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए 1974 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति ने 2.4 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की सिफारिश की थी जिस में से 65,000 एकड़ क्षेत्र टीकमगढ़ जिले में था। उपर्युक्त सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकनों के अनुसार इस सिंचाई-व्यवस्था पर 50.59 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान लगाया गया था जो कि बहुत अधिक था। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई राजघाट नहर परियोजना में, जिस पर 29.67 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, 2.40 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की जानी परिकल्पित है जिस में से 6900 एकड़ क्षेत्र टीकमगढ़ जिले में होगा।

राज्य सरकार टीकमगढ़ जिले में यथा-संभव अधिक से अधिक सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है। इस बीच बेतवा नदी पर 66.82 करोड़ की अनुमानित लागत वाली ओरछा परियोजना सर्वेक्षण कर के तैयार की जा चुकी है। जिससे टीकमगढ़ जिले की सिंचाई तहसील में 29.150 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होने की संभावना है।

Unemployment due to Low Education Standard

3130. SHRI A. ASOKARAJ:
SHRI D. AMAT:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Governments' attention has been drawn to the reported statement of the Chairman, UPSC and published in the *Hindustan Times* of 19th October, 1978 entitled Unemployment due to low education standard'; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). The Government is aware of the statement made by the Chairman, UPSC regarding unemployment due to low standard. The issues raised by the Chairman are receiving the attention of the Government. It is true that not only access but also success in education must be democratised. Improvement of quality of education at all levels is one of objectives of this Government. A revision of the content at all levels has been undertaken mainly with a view to make education useful and relevant.